THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) The estimated cost per unit of power with BHEL equipments is the following:

Tmal plants	Rs. 2.50 crore/MW to Rs. 2.75 crores/MW
Combine cycle power plants	Rs. 2.80 crores/MW

(b) and (c) Information is being collected.

(d) Yes, Sir.

(e) The process for selection of the next incumbent is under way.

Established capacity of BHEL

2394 SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the established capacity in MW for manufacture of Theremal and Hydro Power generating unit of BHEL;

(b) the order position of BHEL for both hydro and hermal power during the next 5 years and the envisaged capacity utilisation thereof;

(c) whether there has been any standardisation of costs per MW for theremal, hydro and combined cycle gas turbine plant of BHEL; and

(d) if so, competitiveness vis-a-vis imported equipments supplied by foreign investors so far in GVK Jegrupadu Project Enron, ST-CMS Energy Neyvelli, etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) The established capacity of BHEL for theremal and hydro power generating equipments is as under—

Thermal	4500 MW/Year
Hydro	1345 MW/Year

(b) The order book position of BHEL at present is about 7800 MW, which would amount to capacity utilisation as under:—

1994-95	1995-96	1996-97
55%	52%	34%

(c) Standarisation of equipment/rating, on which cost/CW is dependent, is being looked into by Central Electricity Authority.

(d) Information is being collected.

खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए गठित समिति

2395. श्री राम लखमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में अगस्त, 1993 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी और उसे खादी और ग्राम उद्योगों के सर्वांगीण विकास के संबंध में सुझाव देने के लिये तीन महीनों की अवधि के भीतर अपने प्रतिवेदन को भेजने का कार्य सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिये गठित समिति द्वारा सुझाव कब दिये गये और वे सुझाव क्या-क्या थे;

(घ) सरकार को इस प्रतिवेदन के अभी तक प्राप्त न होने तथा इसमें हो रहे असाधारण विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा समिति से प्राप्त हुये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं?